नं. जेड-14014/2/2023-जीसी एण्ड पार्लि. (ई-3012849)
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
(भूमि संसाधन विभाग)

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011,
दिनांक: 18.01.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिसंबर, 2022 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को दिसंबर, 2022 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोक्त।

अर्जुन राणा

(अर्जुन राणा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
6. सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
7. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।

10. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. सचिव, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. सचिव, खान मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. सचिव, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. सचिव, व्यय विभाग, नई दिल्ली।
18. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
19. सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
20. सचिव, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
22. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी), भूमि संसाधन विभाग, को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीया राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) के निजी सचिव।
3. माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा इस्पात) के निजी सचिव।

<u>दिसंबर, 2022 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार - के संबंध में।</u>

माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 8 दिसंबर, 2022 को कृषि भवन, नई दिल्ली में "कैक्टस प्लांटेशन और उसके आर्थिक उपयोग" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस बैठक में माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास और इस्पात) और माननीया राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) उपस्थित थे। इस सम्मेलन में ब्राजील, चिली और मोरक्को के राजनयिक ब्राजील, चिली मोरक्को और मैक्सिको से भारतीय राजदूत, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), भूमि संसाधन और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, विभिन्न देशों के कैक्टस के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और विदेश मंत्रालय सहित भिन्न मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त सम्मेलन का उद्देश्य वाटरशेड परियोजनाओं में कैक्टस प्लांटेशन के माध्यम से चारा, ईंधन आदि के अवसरों का पता लगाना था।

2. माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास और पंचायती राज) ने मध्य प्रदेश के अमलाहा में प्रयोगिक परियोजना के रूप में परिकल्पित की जा रही, कैक्टस परियोजना की प्रगति की 20 दिसंबर, 2022 को विभाग में समीक्षा की। क्षेत्रीय निदेशक, अंतरराष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र (आईसीएआरडीए) भी उपस्थित थे।

3. राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) के संबंध में, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने एनजीडीआरएस के राष्ट्रीय पोर्टल के साथ दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित डाटा साझा करना प्रारम्भ कर दिया है, जिससे एनजीडीआरएस से जुड़े राज्यों की कुल संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इस प्रकार एनजीडीआरएस अपनाने वाले राज्यों में पंजाब, अंडमान और निकोबार, मणिपुर, गोवा, झारखंड, मिज़ोरम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, लद्दाख, बिहार, असम, मेघालय, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल हो गए हैं।

4. विशिष्ट भू-खंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) को केरल में प्रारम्भ किया गया है, जिससे यूएलपीआईएन अपनाने वाले राज्यों की कुल संख्या 25 हो गई है। इस प्रकार यूएलपीआईएन अपनाने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, बिहार, ओडिशा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, असम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, तमिलनाडु, पंजाब, दादर और नगर हवेली और दमन और दीप, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केरल शामिल हो गए हैं। यूएलपीआईएन का प्रयोगिक परीक्षण 7 और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों नामत:, कर्नाटक, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार, मणिपुर, दिल्ली, तेलंगाना और लद्दाख में किया गया है।

5. भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर स्कीम के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए सचिव (भूमि संसाधन विभाग) की अध्यक्षता में 06 दिसंबर, 2022 को डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम "भूमि संवाद" पर तीसरा राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का